

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 1 NOVEMBER TO 7 NOVEMBER 2023

**Inside
News**

 अक्टूबर में 1.72
लाख करोड़ रुपये रहा
जीएसटी कलेकशन

Page 3


 देश के अनकनेक्टेड
इलाकों में ऐसे पहुंचेगा
ब्रॉडबैंड स्पीड वाला
इंटरनेट

Page 4



■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 7 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

 चीन की हालत
खस्ता, यूरोप में मंदी की
आशंका लेकिन भारत का
बज रहा दुनिया में डंका


Page 5

editoria!

कतर का संदिग्ध मामला

खाड़ी के देश कतर की एक अदालत ने पिछले सप्ताह भारतीय नौसेना के आठ पूर्व सदस्यों को मौत की सजा सुना दी। इस फैसले से इन लोगों के परिवारों के साथ सरकार भी हैरान है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर दिया 'बहुत स्तब्ध' करने वाला फैसला बताया था। लेकिन, परदेस में अपने संबंधियों के अकेले इतने बड़े संकट में फंस जाने से भारत में उनके घरवाले बहुत बड़ी अनिश्चितता में घिर गये हैं। ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन आठ भारतीयों के परिवारजनों से मुलाकात कर कहा है कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास जारी रखेगी। यह मामला पिछले वर्ष का है, जब अगस्त में आठ पूर्व नौसेनियों को कतर में गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोग कतर की एक डिफेंस सर्विस कंपनी में काम करते थे। इसके बाद इस साल मार्च में मुकदमा शुरू हुआ, और 26 अक्टूबर को उन्हें दोषी ठहराकर मौत की सजा सुना दी गयी। इस मामले में सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह सारी प्रक्रिया गोपनीय और संदिग्ध है। अभी तक यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया है कि इन लोगों पर क्या आरोप थे। मुकदमा भी गुप्त तरीके से चला और किसी गवाह या सबूत का कोई व्यौरा नहीं दिया गया। आठों लोगों के परिवारों और दोहा में भारतीय दूतावास के राजनयिकों के बार-बार अनुरोध के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी गयी। विदेश में भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुना दी गयी, लेकिन इन लोगों के बकीलों और भारत सरकार को उस फैसले की कॉपी तक नहीं दी गयी। गिरफ्तारी के बाद से उनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारियों के आधार पर बताया जा रहा है कि इन लोगों पर एक पनडुब्बी परियोजना की जानकारी तीसरे देश को देने के आरोप हैं। ये मामला पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले की याद दिलाता है। जाधव को वर्ष 2016 में पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन, कतर की स्थिति पाकिस्तान से अलग है क्योंकि उसके साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। कतर में सात लाख भारतीय प्रवासी हैं, जिनका उसकी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। भारत को अपने कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने नागरिकों को रिहा करना चाहिए, और साथ ही उसे यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि ऐसे संदिग्ध मामलों से वहां काम कर रहे भारतीयों के मन में संदेह उत्पन्न होता है, और दोनों देशों का आपसी विश्वास भी कमज़ोर होता है।

नई दिल्ली। एजेंसी

Federal Reserve
Recession Fears-दुनिया भर के शेयर बाजार की निगाहें फेडरल रिजर्व की बुधवार शाम होने वाली कमेंटी पर टिकी हुई हैं। फेडरल रिजर्व के जेरोम पोवेल बुधवार शाम अमेरिका की आर्थिक स्थिति और फेड की मोनेटरी पालिसी पर बयान देने वाले हैं। अगर शेयर बाजार के जानकारों की मानें तो दुनिया इस समय दो धड़े में बटी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है और इसकी इकोनोमी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में तेज वृद्धि और बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े उसके मंदी के दुश्चक्र में फंसने की शुरुआत हो सकते हैं।

आपकी उम्मीद से कहीं कम कीमत पर मुंबई में इको-प्रैफँडली फ्लैट

कुछ और लोगों का मानना है कि अमेरिका में महंगाई दर काबू में आ गई है इसलिए अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व आर्थिक मंदी के संकेत देता है तो इसे दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली बढ़ सकती है। दुनिया भर के इकनॉमिस्ट का मानना है कि अगर अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व आर्थिक मंदी के संकेत देता है तो इसे दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली बढ़ सकती है। इकनॉमिस्ट का मानना है कि साल 2023 में दुनिया के विकसित देशों में आर्थिक मंदी आ सकती है। इसके समय

ग्रोथ को मदद मिल सके। दुनिया भर के उभरते बाजार अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की कमेंटी की वजह से डरे हुए हैं। उन्हें यह आशंका है कि अगर अमेरिका

और इसकी गंभीरता पर हालांकि उनमें अलग-अलग मत हैं। फेडरल रिजर्व बैंक की व्याज दरों से संबंधित पॉलिसी भी अमेरिका में आर्थिक मंदी के संकेत दे



में आर्थिक मंदी की औपचारिक घोषणा या पुष्टि हो गई तो इसे दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली बढ़ सकती है। दुनिया भर के इकनॉमिस्ट का मानना है कि अगर अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व आर्थिक मंदी के दुश्चक्र में फंस चुकी है और अब इकनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए फेडरल रिजर्व व्याज दरों में धीरे-धीरे कटौती करना शुरू कर सकता है।

पिछले दो आर्थिक संकट में केंद्रीय बैंक की व्याज संबंधित नीतियां इसी तरह की रही हैं। वास्तव में कंपनियों के

सीईओ कभी आर्थिक मंदी की बात नहीं करते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि आईटी कंपनियों के अगले दो तिमाही के अनुमान यह जाहिर कर रहे हैं कि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी में फंस चुकी है। इस समय कंपनियों के सीईओ के बयान पर बात करें तो ऐसा लगता है कि कंपनियों का कामकाज मंदी के दौर में फंस चुका है।

ऐतिहासिक रूप से जब अमेरिका में महंगाई की दर बढ़ती हैं तो उसका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजल्ट व्याज दर बढ़ाकर महंगाई को काबू करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है और दुनिया भर पर इसका असर देखा जाता है। इसी तरह जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में फंस जाती है तब फेडरल रिजर्व व्याज दरों में धीरे-धीरे कटौती करता है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू होता है। बुधवार शाम एक बार फिर अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पोवेल इससे संबंधित घोषणा करने वाले हैं जिस पर दुनिया भर के शेयर बाजारों की नज़रें टिकी हुई हैं।

2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा

यूके-फ्रांस को पछाड़ा, अब जापान- जर्मनी की बारी

नई दिल्ली। एजेंसी।

सुधारों की रूपरेखा तैयार करेगा। इसमें व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, पूँजी, अनुसंधान और विकास संस्थाओं पर देश की वैश्विक भागीदारी के बारे में विवरण होने की भी उम्मीद है। वर्तमान में भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (GDP) और अनुमान है कि इस साल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की रहेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जीडीपी 2030 तक जापान और जर्मनी से आगे निकल जाएगी। रेटिंग एजेंसी एसएंडपी का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 2022 में 3.4 ट्रिलियन डॉलर रही। यह 2030 तक बढ़कर 7.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी।

मौजूदा रैंक, देश और उनकी जीडीपी (अरब डॉलर में)

संयुक्त राज्य 26,954

चीन 17,786

जापान 4,231

जर्मनी 4,430

भारत 3,730

यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) 3,332

फ्रांस 3,052

इटली 2,190

ब्राज़ील 2,132

कनाडा 2,122

ब्रिटेन और फ्रांस छह

पीछे अब जापान और

जर्मनी की बारी

सुब्रमण्यम ने कहा, 'आर्थिक

आवश्यकता होगी'

LPG गैस से लेकर बैंकिंग GST तक बदल गए ये 5 नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

1 नवंबर 2023 को नए महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई बड़े बदलाव की भी खबर सामने आ रही है। जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। खासकर पहला बड़ा बदलाव रसोई गैस की कीमत को लेकर देखने को मिला है। इसके बाद बीमा धारक को और कारोबारी से जुड़े बदलाव देखने को मिले हैं तो आईए जानते हैं कि इस महीने कौन 5 बड़े बदलाव को लेकर फैसला लिया गया है?

पहली नजर LPG की कीमत पर

हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमत को लेकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कुछ नया संशोधन करती हैं। ऐसे में इस महीने की शुरुआत और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सरकार भी रसोई गैस की कीमत को लेकर लोगों को राहत देने का फैसला लिया है। जिसके बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने कीमत में कुछ उत्तर-चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है।

GST का नंबर दूसरा

1 नवंबर 2023 से बदले गए जीएसटी के नियम में यह सबसे बड़ा बदलाव राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से 100 करोड़ से अधिक के कारोबार करने वाले कारोबारी को 30 दिन के अंदर ई-चालान पोर्टल पर जाकर जीएसटी चालान को अपडेट करना होगा।

BSE ट्रांजैक्शन को लेकर भी चर्चा

दरअसल, पहली सत्र में इकिवटी के डेरी बेटी से कर्मेंट मेरा इंजेक्शन शुल्क वो बढ़ाने को लेकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की ओर से फैसला लिया गया था। जिसे अब 1 नवंबर 2023 लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अब शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को इसका असर देखने को मिल सकता है।

बीमाधारक के लिए खास खबर

अगला और चौथा सबसे बड़ा बदलाव बीमाधारकों को लेकर है। यानी अब से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की ओर से सभी बीमा धारक के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।

इस महीने बंद रहेंगे 15 दिन बैंक

आरती रिजर्व बैंक की ओर से नंबर महीने में अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग बैंक को तमाम त्योहारी सीजन को देखते हुए बंद रखा जाएगा। जिसमें छठ पूजा, दिवाली, भाई दूज जैसे कई पावन पर्व के उपलक्ष में 15 दिनों के लिए सभी बैंक बंद रहेंगे। इसीलिए आप बैंक से जुड़े सभी काम को अभी जाकर करवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इजरायल-हमास संघर्ष के बीच विरोध प्रदर्शनों से बेकाबू हो रहे ब्रिटेन के हालात

पीएम ऋषि सुनक ने उठाया ये कदम

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजरायल-गाजा संघर्ष के बीच और देश की सड़कों पर व्यापक प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि से चिंतित हो उठे हैं। गाजा में इजरायली हमले के खिलाफ ब्रिटेन में लगातार फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन पुलिस को इन हालातों पर काबू पाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। ऐसे में हालात लगातार चिंताजनक होते जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के लिए घरेलू सुरक्षा मुद्रों का विश्लेषण करने के लिए सामवार को लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।

यह कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग

रूम्स ए' (कोबरा) बैठक ऐसे समय में हो रही है जब एक और सप्ताहांत में हजारों लोगों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के खिलाफ प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के दौरान नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और पांच पर सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। बैठक में ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी शामिल हुई।

ब्रिटेन में हमला कर सकते हैं प्रदर्शनकारी

ब्रिटेन सरकार ने अपने देश में हमले की आशंका जतायी है। मेट्रोपोलिटन पुलिस के अनुसार, तीन सप्ताह पहले पश्चिम एशिया में संकट गहराने के बाद से देश में यहूदी विरोधी घटनाओं में 14 गुना बढ़ि हुई है खबरों के अनुसार, ब्रिटेन सरकार देश में प्रदर्शन से जुड़ी कुछ चरमपंथी चिंताओं से निपटने के लिए आतंकवाद संबंधी कानूनों को कड़ा करने के तरीकों पर विचार कर सकती है। ब्रेवरमैन ने ऐसी घटनाओं के खिलाफ कड़ी

मार्क रॉवले ने ब्रिटेन की सड़कों पर चरमपंथ से निपटने के लिए "सख्त" कानून बनाने का आह्वान किया था। प्रदर्शन के दौरान नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया और पांच पर सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। बैठक में ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी शामिल हुई।

पुलिस कार्रवाई न करने को लेकर सवाल किया जबकि पुलिस ने आगाह किया कि ऐसे मामलों के खिलाफ कानून को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है।

लंदन में 100 से अधिक प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

इस माह के शुरू में इजरायल-

समाचार

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

2 हजार के नोट के बाद RBI ने 1 और 10 रुपये के सिक्के को लेकर किया Notification जारी

नई दिल्ली। एजेंसी

आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ दुकानदार 10 रुपये का सिक्का या एक रुपये का छोटा वाला सिक्का लेने से इनकार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि 10 रुपये के सिक्के नकली हैं या कि एक रुपये के सिक्के अब नहीं हैं। अगर आपके पास भी एक और दस रुपये के सिक्के हैं, तो आप इस सूचना को पढ़ सकते हैं। दरअसल, आरबीआई ने हाल ही में जारी किए गए दो हजार रुपये के नोट के बाद एक और दस रुपये के सिक्के का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको कई बार

माशिकल भी होंगी। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा करना कानून अपराध है और आप उन लोगों की शिकायत करते हैं तो उन्हें सजा भी मिल सकती है। ऐसे में आप जानते हैं कि आप किस तरह शिकायत कर सकते हैं अगर ऐसा होता है। साथ ही सिक्का लेने के नियमों और सजा के बारे में भी जानिए। सिक्कों के नियमों को जानें...।

क्या सजा का प्रावधान है?

यदि कोई व्यक्ति सिक्का लेने से मना करता है (यदि सिक्का चलन में जारी किए गए दो हजार रुपये के नोट के बाद एक और दस रुपये के सिक्के का नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए), तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जा सकती है। भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।

जाएंगी। रिजर्व बैंक भी मामले की शिकायत कर सकता है। दुकानदार या कोई भी व्यक्ति जो सिक्के लेने से इनकार करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

आरबीआई ने भी जानकारी दी थी?

जैसे, रिजर्व बैंक ने भी सिक्कों को लेकर जानकारी दी थी और कहा था कि कोई भी सिक्के नकली नहीं थे। साथ ही, आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्कों के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही थीं, वे गलत थीं। ऐसे में आप किसी भी 10 रुपये के सिक्कों को लेन-देन में ले सकते हैं। ध्यान दें कि भारतीय रिजर्व बैंक को 10,000 रुपये से लेकर 2 रुपये के नोट बनाने का अधिकार है। आरबीआई के बजाय वित्त मंत्रालय एक रुपये का नोट छापता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।

एचडीएफसी इर्गो ने रबी सीजन में मप्र के किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना लागू की

इंदौर। आईपीसी नेटवर्क

भारत में निजी क्षेत्र की अग्रणी सामान्य बीमा कंपनी, एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने रबी, 2023 सीजन के लिए अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा और खरगोन जिलों में ऋणी और गैर-ऋणी किसानों के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) लागू करने के लिए अधिकृत किया है। इन जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अधिसूचित निम्नलिखित फसलों के लिए किया जाएगा, जिनके लिए फसलों के अनुसार कट-ऑफ तिथियाँ निम्नलिखित हैं:

पीएमएफबीवाई योजना में किसानों को तूफान, ओलावृष्टि, बाढ़, तूफानी बारिश, बेमौसम बारिश, बादल फटने, प्राकृतिक कारणों से लगी आग जैसे कई बाहरी खतरों के कारण फसल को होने वाले नुकसान से बीमा की सुरक्षा मिलती है। फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) की योजना बनाकर संचालन करेगी। यदि सीसीई में फसल के कम आंकड़े पाए

HDFC ERGO

में अपने बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या फिर अधिकृत एचडीएफसी इर्गो एजेंट्स से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। बीमा कवर प्राप्त करने की अंतिम तिथि का वर्णन एवं अन्य विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। किसान ऐप पर लॉगओन करके या वेबसाइट <https://pmfby.gov.in/farmerLogin> पर इस योजना में सेल्फ-एनरोलमेंट द्वारा भी किसान इसका लाभ ले सकते हैं।



पुलिस कार्रवाई न करने को लेकर सवाल किया जबकि पुलिस ने आगाह किया कि ऐसे मामलों के खिलाफ कानून को पूरी तरह परिभाषित नहीं किया गया है।

बीच, ब्रिटेन के अपराध और पुलिसिंग मंत्री क्रिस फिलिप ने देश के पुलिस प्रमुखों को पत्र लिखकर उनसे अपराधियों को पकड़ने के लिए चेहरे की पहचान करने वाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस तकनीक का इस्तेमाल कर छापेमारी की संख्या दोगुनी करने को कहा है।

अक्टूबर में 1.72 लाख करोड़ रुपये रहा जीएसटी कलेक्शन



नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जीएसटी के आंकड़े जारी किए। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल के बाद दूसरी बार सबसे अधिक जीएसटी संग्रह अक्टूबर में हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह अक्टूबर में सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

जीएसटी चोरी रोकने के सख्त उपाय और त्योहार के दौर में उपभोक्ताओं के अधिक खरीदारी करने के कारण जीएसटी संग्रह बढ़ा है।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जीएसटी के आंकड़े जारी किए। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल के बाद दूसरी बार सबसे अधिक जीएसटी संग्रह अक्टूबर में हुआ। अप्रैल में सबसे अधिक जीएसटी

संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये हुआ था। यह सितंबर में 1.63 लाख करोड़ रुपये रह गया था।

मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में औसत मासिक जीएसटी संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। यह लगातार आठवां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। अक्टूबर के दौरान घेरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) बीते साल के इस महीने की तुलना में 13 फीसदी अधिक रहा।

डेलाइट इंडिया के पार्टनर एमएस मणि ने कहा, 'बीते कुछ महीनों के दौरान जीएसटी संग्रह महत्वपूर्ण रूप से मजबूत हुआ है। यह केवल मजबूत आर्थिक कारकों

के कारण ही नहीं बढ़ा है बल्कि कर अधिकारियों के कर चोरी रोकने के उपायों पर अंकुश लगाने से हुआ है। कर अधिकारियों ने छोटे भुगतान के आंकड़ों का विभिन्न तरीकों से विश्लेषण किया है।'

अक्टूबर, 2023 में कुल जीएसटी राजस्व 1.72 लाख करोड़ रुपये है। इसमें केंद्रीय जीएसटी 30,062 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 38,171 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी (माल आयात पर एकत्र 42,127 करोड़ रुपये सहित) 91,315 करोड़ रुपये और उपकर 12,456 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर एकत्र 1,294 करोड़ रुपये सहित) हैं। सरकार ने आईजीएसटी में सीजीएसटी के 42,873 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के

36,614 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद अक्टूबर में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 72,934 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 74,785 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय एजेंसी में अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख व साझेदार अभियंकर जैन ने कहा, 'वित्त वर्ष 17-18 के निपटान की सामान्य अवधि 30 सितंबर को समाप्त हुई थी जो जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। वित्त वर्ष के मध्यम में ऐसा बढ़ा हुआ संग्रह होना निश्चित रूप से उत्साहजनक है और त्योहार के दौरान राज्यों में 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः 14 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

अनुमान जताया है कि त्योहारी मौसम में जीएसटी संग्रह बढ़ने का दौर जारी रह सकता है। इवाईके टैक्स पार्टनर सौरभ अग्रवाल के अनुसार, 'इस महीने में जीएसटी संग्रह बढ़ना भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित कर सकता है।'

राज्यवार संग्रह

देश के राज्यों के दौरान राज्यवार संग्रह के दौरान राज्यवार अधिकारियों में जामू एवं कश्मीर, मिजोरम, लद्दाख, लक्ष्मीप, मेघालय, सिक्किम आदि में उपभोग और कर का आधार बढ़ा है। इस महीने के दौरान राज्यों में 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में क्रमशः 14 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

स्काईस्कैनर ने अगले साल के लिए यात्रा के रुझानों का खुलासा किया

साथ लाखों सर्च एवं प्रोप्राइटरी उड़ानों और होटल के आंकड़ों के साथ उपभोक्ताओं के वार्षिक व्यवहार के अध्ययन एवं विशेषज्ञों की विप्पणी भी पेश की गई।

इन परिणामों के बारे में स्काईस्कैनर ट्रैवल ट्रेंड्स एंड डेस्टिनेशन विशेषज्ञ, मोहित जोशी ने कहा भारतीय यात्रियों में खोजने और समृद्ध एवं ज्यादा संतोषजनक अनुभवों के साथ छुट्टियों का पूरा आनंद लेने की इच्छा साफ है क्योंकि वो (63प्रतिशत) 2024 में यात्रा पर ज्यादा खर्च करने की योजना गंतव्यों का खुलासा किया, जिसके

बना रहे हैं। अगले साल सांस्कृतिक खोज पर ध्यान केंद्रित करने के साथ भारत में यात्रा की मजबूत मांग का कारण स्काईस्कैनर जैसा ट्रैवल मेटासर्च भारतीयों को बेहतरीन मूल्य प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, इसमें 'एक्स्प्लोर एवरीहेयर' सर्च फीचर का उपयोग कर मूल्य के आधार पर स्थानों को तलाशा जा सकता है। स्काईस्कैनर के टूल्स की मदद से यात्रियों को मोलभाव करने के कई तरीके मिलते हैं, ताकि वो उन्हीं सुविधाओं के लिए भुगतान करें,

जो वो चाहते हैं।' रिपोर्ट के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि फिल्म और मनोरंजन का भारतीय यात्रियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 94प्रतिशत भारतीय उन जगहों पर जाना चाहते हैं, जो वो बड़े या छोटे पर्दे पर देखते हैं। इसके अलावा, लगभग आधे (43प्रतिशत) उत्तरदाता 2024 में कहाँ जाना है, यह निर्णय लेने के लिए उस जगह की 'वाइब'

को महत्व देते हैं।

अमेरिकी डॉलर हुआ मजबूत तो भारतीय करेंसी पर दिखा इसका असर

नई दिल्ली। एजेंसी

शेयर बाजार में गिरावट और अमेरिकी डॉलर में हुई वृद्धि ने भारतीय करेंसी को प्रभावित किया है। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ खुला है। वहीं शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में पूरे साल के लक्ष्य का 39.3 प्रतिशत तक पहुंच गया।

टाटा मोटर्स की सीएसआर पहल से पिछले दशक में 60 लाख से अधिक लोगों को लाभ वित्त वर्ष 23 के लिए 9वीं वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट जारी

मुंबई। एजेंसी

भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी, टाटा मोटर्स ने आज अपनी 9वीं वार्षिक सीएसआर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य (आरोग्य), शिक्षा (विद्याधनम), नियोजनीयता (कौशल्य) और पर्यावरण (वसुधरा) के क्षेत्रों में भारत के सबसे गंभीर और सामाजिक चुनौतियों को हल करने की दिशा में व्यापक प्रयासों पर रोशनी डाली गई है। सामूहिक रूप से, इन प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में 60 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है और इन लाभार्थियों का एक बड़ा हिस्सा हाशिये पर पढ़े समुदायों से आता है।

वर्ष 2014 में, टाटा मोटर्स ने देश भर में अपनी सीएसआर पहलों को एक समान सुसंगत करने



विशेषज्ञता की बढ़ावत स्पष्ट निर्धारित परिणामों और उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ फोकस्ड मध्यवर्तनों का निर्माण और कार्यान्वयन किया गया। सभी स्थानों में कार्यक्रमों में समरूपता, डिजिटल तकनीकों का लाभ, विविध हितधारकों के साथ साझेदारियों को

बढ़ावा देना और समुदायों के साथ भरोसे की मजबूती के द्वारा कंपनी ने अनुमानित प्रभाव से काफी अधिक प्रभाव पैदा किया है। इस अवसर पर टाटा मोटर्स के सीएसआर हेड, श्री विनोद कुलकर्णी ने कहा कि, 'टाटा मोटर्स में हमारे सीएसआर संबंधी प्रयास समावेशी विकास को बढ़ावा देने और इस प्रकार राष्ट्र-निर्माण में योगदान करने के प्रति हमारी अडिग वचनबद्धता के साथ गहराई से जुड़े हैं। हमें अपने प्रयासों से लाखों लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालकर बहुत खुशी हो रही है। असल में, सीएसआर से सम्बंधित हमारे अनेक विचार और कार्यक्रम में से अनेक विश्वाल परियोजनायें हो गई हैं, जो सामुदायिक विकास के लिए मॉडल के रूप में अनुकरणीय हैं।'

विशेषज्ञता की बढ़ावत स्पष्ट निर्धारित परिणामों और उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ फोकस्ड मध्यवर्तनों का निर्माण और कार्यान्वयन किया गया। सभी स्थानों में कार्यक्रमों में समरूपता, डिजिटल तकनीकों का लाभ, विविध हितधारकों के साथ साझेदारियों को



विज्ञापन के लिए संपर्क करें।
83052-99999
f t e indianplasttimes@gmail.com



देश के अनकनेक्टेड इलाकों में ऐसे पहुंचेगा ब्रॉडबैंड स्पीड वाला इंटरनेट

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश के दूरदराज के इलाकों, ठेठ ग्रामीण या जंगलों में बसे गांवों में भी अब ब्रॉडबैंड की स्पीड वाला इंटरनेट करने वाले वैश्वन यहुं चोगा। इन इलाकों को कनेक्ट करने के लिए रिलायंस जियो 'जियो स्पेस फाइबर' नाम की एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका प्रदर्शन आज से याहां बें प्रगति मैदान में शुरू हुए इंडिया मोबाइल कंग्रेस में किया गया है। इस तकनीक का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया।

क्या है स्पेस फाइबर तकनीक

रिलायंस जियो की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक 'जियो स्पेस फाइबर' सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर टेक्नोलॉजी है। यह उन दुर्गम और दूर-दराज के इलाकों को कनेक्ट करेगा जहां फाइबर केबल से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना मुश्किलों भरा काम है। कंपनी का दावा है कि यह सर्विस पूरे देश में अत्यधिक किफायती कीमतों पर उपलब्ध होगी।

देश के चार राज्यों में हो

गई सेवा शुरू

कंपनी का कहना है कि देश



के चार सबसे दूरस्थ स्थानों को जियो स्पेस फाइबर से जोड़ा जा चुका है। इनमें गुजरात का गिरनेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ का औद्योगिक शहर कोरबा, उड़ीसा का नबरंगपुर और असम का ओएनजीसी-जोरहाट शामिल हैं।

इजरायल-हमास युद्ध से नुकसान के साथ भारत को ये फायदे भी

दवा इंडस्ट्री के लिए मौका-मौका

नई दिल्ली। एजेंसी

हमास आतंकियों के हमले के बाद से इजरायल की जबाबी कार्रवाई लगातार जारी है। इजरायल से तय कर लिया है कि जब तक वो हमास आतंकियों को खत्म नहीं कर देता युद्ध जारी रखेगा। युद्ध वैसे तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन इजरायल हमास के बीच जारी इस जंग से कई फायदे भी छिपे हैं। ग्लोबल इकॉनमी के दौर में हर देश दूसरे से लिंक है। ऐसे में जंग का असर केवल इजरायल और फिजिस्तीन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। अगर भारत के हिसाब से देखे तो युद्ध के कारण महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इस जंग से कुछ फायदे भी होंगे।

इजरायल युद्ध से फायदे

ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल में कई वैश्विक टेक कंपनियों के दफ्तर हैं। अगर युद्ध लंबा चला तो इन कंपनियों का

एसईएस कंपनी के उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी 'जियो स्पेस फाइबर' से अब कहीं भी और कभी भी विश्वसनीय मल्टी-गीगाबिट कनेक्टिविटी मिलेगी। चुनौती भरे इलाकों में उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवाओं को पहुंचाने के लिए 'जियो स्पेस फाइबर' इनोवेटिव एंड एडवांस न्यूएच तकनीक का उपयोग करेगा।

क्या कहना है छोटे

अंबानी का

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अध्यक्ष आकाश अंबानी ने कहा, 'जियो ने भारत में लाखों घरों और व्यवसायों को पहली बार ब्रॉडबैंड इंटरनेट का

लिए विकल्प बन सकते हैं। जिस तरह से बीते कुछ सालों से भारत विदेशी कंपनियों की पहली पसंद बनकर उभरा है, इसका फायदा उसे यहां भी मिल सकता है।

फार्मा कंपनियों को फायदा

इजरायल हमास युद्ध से भारत की फार्मा कंपनियों के लिए नए मौके खुल सकते हैं। युद्ध और तनाव के चलते पश्चिम एशिया के कई देशों के दवा उद्योगों के सामने संकट है। यूएई, बहरीन, ओमान, कतर जैसे देश आयात पर निर्भर हैं। युद्ध के कारण इस देशों का करीब 1 बिलियन डॉलर का दवा व्यापार प्रभावित हो सकता है। ऐसे में ये देश भारत की फार्मा इंडस्ट्री का मुहं ताक सकती है। उनके लिए ये मौका हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस युद्ध का भारत पर असर नहीं पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत में तेजी से देश में महंगाई बढ़ सकती है। आयात-निर्यात प्रभावित हो सकता है।

प्याज से आंसू थामने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, निर्यात को लेकर नया ऐलान

नयी दिल्ली। एजेंसी

पहले टामाटर और अब प्याज की बढ़ती कीमत से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार प्याज के दाम में आ रही तेजी को थामने के लिए ठोस कदम उठाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत पर ब्रेक लगाने के लिए शनिवार को बड़ा फैसला किया। प्याज के निर्यात को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार ने घेरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को इस प्रमुख सब्जी के निर्यात पर 31 दिसंबर, 2023 तक 800 डॉलर प्रति टन किया जाता है।" एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इस कदम से घेरेलू उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर प्याज की पर्याप्ति

उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी क्योंकि रबी 2023 के लिए भंडारित प्याज की मात्रा में गिरावट आ रही है। प्याज के लिए 800 डॉलर प्रति टन एमईपी लगभग 67 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर होता है। अगस्त के दूसरे सप्ताह से देशभर के प्रमुख उपभोक्ताओं में बफर स्टॉक से प्याज को लगातार निकाला गया है, और एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा संचालित मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति भी की गई है। बयान में कहा गया है, "अब तक बफर स्टॉक से लगभग 1.70 लाख टन प्याज का निपटान किया जा चुका है। उपभोक्ताओं के

लिए कीमतों को नियंत्रित करने और प्याज किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की निरंतर खीरी और निपटान किया जाता है।" कम आपूर्ति के कारण राष्ट्रीय राजधानी के खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें बढ़कर 65-80 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लगभग 400 सफल खुदरा स्टोर वाली मदर डेयरी 67 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खुला प्याज बेच रही है। वहां ई-कॉर्मस पोर्टल बिगबास्टेट पर यह 67 रुपये प्रति किलो की दर पर है। स्थानीय विक्रेता 80 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेच रहे हैं।

डॉ. द्विवेदी बने वित्त में निकाय

(प्रबंधकीय बोर्ड) सदस्य

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क



मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय) द्वारा उज्जैन स्थित अवंतिका विश्वविद्यालय के शासी निकाय में डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी प्रोफेसर एवं समूह निदेशक, (मॉर्डन युप ऑफ इंस्टीट्यूट्स इंदौर) का मनोनयन किया गया है। इस उपलब्धि पर इंदौर और उज्जैन संभाग के शिक्षाविदों एवं समाजसेवियों में डॉ.

पुनीत द्विवेदी को बधाई दी है। जात हो कि, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत डॉ. पुनीत द्विवेदी का मनोनयन हुआ है। डॉ. द्विवेदी उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के नॉमिनी के रूप में अपनी सेवायें देंगे। बताते हुए कि विवेदी उद्यमिता उच्च शिक्षा एवं फार्मासीस्टूडिक्स शिक्षा के क्षेत्र में मज़बूत पकड़ रखने वाले डॉ. द्विवेदी के नाम 16 पेटेंट प्रकाशित हैं। उद्यमिता एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में 21 से अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन डॉ. द्विवेदी ने किया है। इंदौर स्वच्छता के ब्रांड एंबेस्टर के रूप लगातार 7 वर्षों से अपनी सेवायें दे रहे हैं। डॉ. पुनीत द्विवेदी सविष्ठकार मालवा के प्रमुख एवं राज्यपाल द्वारा किया गया है। डॉ. पुनीत द्विवेदी सविष्ठकार मालवा के प्रमुख एवं राष्ट्रीय मैटर की भूमिका में हैं।

चीन की हालत खस्ता, यूरोप में मंदी की आशंका लेकिन भारत का बज रहा दुनिया में डंका

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर उत्साहित करने वाली कई खबरें आ रही हैं। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन ने सरकार की झोली भर दी है। यह अब का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन है। अक्टूबर में कार कंपनियों की बिक्री में काफी तेजी आई है। इस साल अब तक रेकॉर्ड 149 कंपनियों के आईपीओ आ चुके हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत इस साल भी दुनिया की सबसे तेज इकॉनमी बना रहेगा। अभी भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और जल्दी ही यह तीसरे नंबर पर पहुंच सकती है। दूसरी ओर चीन की इकॉनमी संघर्ष कर रही है जबकि यूरोप एक बार फिर मंदी के साए में जी रहा है।

चौका देंगे आंकड़े

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दावा किया है कि चालू वित्त वर्ष दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े सभी को चौका देंगे। उन्होंने कहा की आर्थिक गतिविधियों

की गति और कुछ शुरुआती संकेतक इसका इशारा दे रहे हैं। दास ने कहा कि दुनिया में संघर्ष के नए केंद्र उभर रहे हैं जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ को लेकर सबसे बड़ा जोखिम पैदा करते हैं। लेकिन ऐसी जोखिम भरी स्थितियों से निपटने के लिए भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य साल 2028 तक वर्ल्ड ग्रोथ में 18% तक योगदान देना है।

जीएसटी कलेक्शन

अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 13 बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह जीएसटी कलेक्शन का दूसरा सबसे ऊंचा मासिक अंकड़ा है। पिछले साल अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा था। अप्रैल, 2023 में जीएसटी संग्रह औल टाइम हाई 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा था जबकि सितंबर में यह 1.63 लाख करोड़ रुपये था। इक्रा की चीफ इकाइनैमिस्ट अदिति नायर ने कहा कि अर्थव्यवस्था की



रस्तार से जीएसटी संग्रह बढ़ा है। अक्टूबर 2023 में साल-दर-साल बढ़ोतारी की गति 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो उत्साहजनक है। अनुमान है कि सीजीएसटी संग्रह चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान से थोड़ा अधिक होगा।

कारों की रेकॉर्ड बिक्री

अक्टूबर में कारों की बिक्री रेकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। अक्टूबर में कारों की थोक बिक्री औल टाइम हाई पर 16% बढ़कर 3,91,472 यूनिट पर पहुंच गई, जो पिछले साल के इसी महीने में 3,36,679 यूनिट थी। अक्टूबर में देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी

मारुति सुजुकी इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घरेलू बाजार में अब तक की सबसे अधिक बिक्री दर्ज की। दू वीलर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने अक्टूबर में सालाना आधार पर 26.5% बढ़ोतारी दर्ज करते हुए 5,74,930 वाहन बेचे। होंडा की बिक्री 10%, सुजुकी 14.4% और रॉयल एनफील्ड की अक्टूबर में बिक्री 2.68% बढ़ी।

सबसे ज्यादा आईपीओ

इस साल दुनिया में सबसे ज्यादा आईपीओ भारत में आए हैं। इवाई की एक स्टडी के मुताबिक सितंबर तक भारत में 149 आईपीओ लिस्ट हो चुके हैं। त्योहारी सीजन

में यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है क्योंकि इस महीने कई कंपनियों के आईपीओ खुलने वाले हैं। पिछले साल कुल 144 कंपनियों के आईपीओ आए थे। सितंबर तिमाही में 21 कंपनियां आईपीओ लेकर आई और इनसे 1.7 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई गई। पिछली तिमाही में एसएमई सेगमेंट में भी काफी रौनक रही और कुल 48 कंपनियों ने 16.6 करोड़ डॉलर जुटाए।

चीन की हालत

इस बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चीन की हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। रियल एस्टेट संकट के कारण पूरी इकॉनमी के डब्बने का खतरा पैदा हो गया है। चीन की इकॉनमी में इस सेक्टर की करीब 30 फीसदी हिस्सेदारी है। सरकार ने इसमें जान छूकने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं लेकिन अब तक उसे निराशा ही हाथ लगी है। देश के लोग पैसे खर्च करने के बजाय बचाने में लगे हैं जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग में गिरावट आई है। मांग कम होने से तरह प्रभावित हुई है।

भारत में कौशल की कमी दूर करने के लिए

16.2 मिलियन कर्मचारियों को एआई और ऑटोमेशन में अपस्किल की ज़रूरत

सर्विसनाऊ के नए शोध में सामने आई यह बात

गई है।

भारत में उन नौकरियों की पदस्थापना में, जिनमें सर्विसनाऊ प्लैटफॉर्म तकनीकी कौशल की ज़रूरत है, पिछले साल 39% की वृद्धि हुई। लाइटकास्ट के श्रम बाज़ार के आंकड़ों के अनुसार यह पूरे विश्व में सबसे तेज वृद्धि दर है जहाँ पूरे विश्व के किसी भी शहर की अपेक्षा बैंगलोर में टैलेंट के लिए सबसे ज्यादा माँग देखी गई। भारत का डिजिटल स्किल इकोसिस्टम भी इसके साथ वृद्धि करने को तैयार है। सर्विसनाऊ के भारतीय उपमहाद्वीप के लिए वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक, कमोलिका गुप्ता पेरेस ने कहा कि, 'भारत के निर्णय-निर्माता और उद्योग के दिग्गज एआई की शक्ति को समझते हैं। हम व्यवसाय में सार्थक बदलाव के लिए एआई की प्रयोग की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां प्रदर्शित करने के लिए पूरे देश में हर एक उद्योग के साथ काम कर रहे हैं। हम इन बदलावों से लोगों के लिए सार्थक, गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित कैरियर प्राप्त करने के साथ-साथ बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दे रहे हैं।'



दुनियाभर पर होगा असर

में बढ़ोतारी होगी। ये बढ़ोतारी 150 से 157 डॉलर प्रति बैरक तक पहुंच सकती है।

भारत पर भी असर

वर्ल्ड बैंक की चेतावनी के मुताबिक अगर युद्ध जारी रहा और कच्चे तेल की कीमत में तेजी आई तो भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में महंगाई और बढ़ा जाएगी। वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक जंग के कारण कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर बैरल से ऊपर पहुंच सकती है। ऐसा होने पर एनर्जी और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में असमान्य उछाल देखने को मिल सकता है। यूक्रेन-रूस युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विघटनकारी प्रभाव देखने को मिला था। अब एक बार फिर से वर्ही स्थिति बन रही है। तेल की कीमतों में तेजी का मतलब है सीधे खाद्य पदार्थों की कीमत में तगड़ा उछाल। खाद्य मूल्य बढ़ने का मतलब है सीधी आम जनता पर इसका असर होना। चूंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात करता है, ऐसे में कच्चे तेल की कीमत में असर होने पर भारत की आपूर्ति कम होने पर कीमती वाली खाद्य पदार्थों की चीजों और मंहगी हो जाएगी।

और हमास युद्ध का असर तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। बुधवार को क्रूड ऑयल के रेट में लगभग 2 फीसदी की बढ़ोतारी हुई है।

महंगाई की बढ़ेगी मार

इस युद्ध का असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। डायमंड और ज्लैवरी पर भी इस जंग का असर होगा। इजरायल के मुताबिक जंग के कारण कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर बैरल से ऊपर पहुंच सकती है। ऐसा होने पर एनर्जी और फूड प्रोडक्ट्स का ली डर कहलाने वाला भारत पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के कई देशों को बड़े पैमाने पर दवा का निर्यात करता है। युद्ध के कारण इसमें विक्रित आ सकती है। इतना ही नहीं इजराइल-हमास युद्ध के कारण भारत के बड़े कारोबारी घराने, जिसका कारोबार इजरायल में फैला है, उन्हें दिक्कत हो सकती है। युद्ध लंबा चला तो की मुश्किलें आम आदमी तक पहुंच जाएंगी। बचत, घर या कार के लोन की किस्त, निवेश से लेकर रोजमरा की चीजों और मंहगी हो जाएंगी। इजराइल में नौकरियों पर असर होगा।

बढ़ने वाला है आपके मोबाइल का बिल!

नई दिल्ली। एजेंसी

टेलिकॉम कंपनियां एक बार फिर आपके मोबाइल का बिल बढ़ाने की फिराक में हैं। देश की दो बड़ी टेलिकॉम कंपनियां एयरटेल (Airtel) और वोडा आइडिया (Voda Idea) एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी करना चाहती हैं लेकिन देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो इसके पक्ष में नहीं है। जियो का कहना है कि वह टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं करेगी। कंपनी का कहना है कि वह 5जी कस्टमर्स के लिए भी टैरिफ बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। कंपनी का

नजर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल/एमटीएनल के उन 24 करोड़ ग्राहकों पर है जो अब भी 2जी नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिलायंस जियो के प्रेजिडेंट मैथ्यू ऊमन ने कहा कि कंपनी की योजना टैरिफ में बढ़ा बदलाव करने की नहीं है। कंपनी का फोकस ऐसे ग्राहकों पर है जो डेटा प्लान की तरफ आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी का यही विजन है। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ से अधिक कस्टमर अब भी 2जी का

इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें डिजिटली सशक्त बनाने की जिम्मेदारी इंडस्ट्री की है। देश को 2जी-मुक्त बनाने का एकमात्र तरीका यही है कि सस्ते में सेवा दी जाए।

एआरपीयू क्या है

ऊमन ने कहा कि सभी भारतीयों की डेटा तक पहुंच होनी चाहिए। हम उन्हें इससे बंचित नहीं रख सकते हैं। हम सभी भारतीयों को सुपीरियर कस्टमर एक्सप्रीयंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी देना चाहते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को किसी भी टेलिकॉम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्प का अहम पैमाना माना जाता है। दूसरी तिमाही में जियो का एआरपीयू 181.7

रुपये पहुंच गया जो पिछले साल की समान तिमाही में 177.2 रुपये था और पिछली तिमाही में 180.5 रुपये था। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ बढ़ाने की वकालत की है। उनका कहना है कि कैपेक्स बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

भारती एयरटेल के सीईओ गोपाल विड्ल ने कहा, 'हम इंडस्ट्री के लिए एट्रेटर फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत पूँजी खर्च हो रही है। इसलिए एआरपीयू में बढ़ोतरी जरूरी है।' उनका कहना है कि एआरपीयू 300 रुपये तक होना चाहिए। पहली

तिमाही के अंत में एयरटेल का एआरपीयू 200 रुपये था जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। वहीं भारी कर्ज में ढूबी वोडाफोन आइडिया का दूसरी तिमाही में एआरपीयू मात्र 142 रुपये था। इससे साफ है कि वोडाफोन आइडिया को खुद को रेस में बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। हम इंडस्ट्री के लिए एट्रेटर फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत पूँजी खर्च हो रही है। इसलिए एआरपीयू में बढ़ोतरी जरूरी है।

गोपाल विड्ल, सीईओ, भारती एयरटेल

स्पेक्ट्रम पर मतभेद स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले पर भी टेलिकॉम कंपनियों के बीच एक राय नहीं है। रिलायंस जियो ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की वकालत की है जबकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉकेशन की मांग कर रही हैं। जियो ने देश में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की एंट्री का भी स्वागत गिया है। दुनिया के सबसे बड़े रईस मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज देना चाहती है। लेकिन उसे अब तक सरकार की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है।

कोलगेट-पामोलिव भारत में ओरल केयर के मानक बढ़ाने में

सबसे आगे; 'मीठा सच' (स्वीट ट्रूथ) साझा किया

रात में दाँत साफ करने की सेहतमंद आदत को प्रोत्साहित करने का मिशन शुरू किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोलगेट-पामोलिव भारत में ओरल केयर के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। उनका कोलगेट ब्राइट स्माइल्स, ब्राइट फ्यूचर्सरु कार्यक्रम देश में 171 मिलियन से ज्यादा बच्चों को ओरल केयर की स्वस्थ आदतों का विकास करने के लिए प्रोत्साहित कर चुका है। इसी उद्देश्य के अनुरूप, कोलगेट अपने मिशन द्वारा अब रात में दाँत साफ करने की सेहतमंद आदत को बढ़ावा दे रहा है। भारत में हर 10 में से 9 लोगों को कैविटी है, जिससे ओरल केयर की दिनचर्या बनाए रखने की आपात ज़रूरत प्रदर्शित होती है। वैज्ञानिक प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि सुबह के अलावा रात में भी दाँतों को ब्रश करने से दाँत स्वस्थ बने रहते हैं। इस साधारण आदत की मदद से कैविटी होने की सम्भावना 50% से घट जाती है। कोलगेट-पामोलिव ने देश में ओरल स्वास्थ्य

में सुधार लाने के लिए रात में ब्रश करने के महत्व का प्रसार करने का दायित्व संभाला है।

कोलगेट-पामोलिव इंडिया की एमडी एवं सीईओ, प्रभा नरसिंहन ने कहा, 'मार्केट लीडर के रूप में भारतीयों को ओरल केयर की स्वस्थ आदतों का विकास करने का प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य भी है, और दायित्व भी। ओरल स्वास्थ्य की ओर हमारी प्रतिबद्धता जीवन के हर पहलुओं तक विस्तृत है। मैं रात में ब्रश करने के अत्यधिक महत्व पर बल देती हूँ। त्योहारों के मौसम में तो यह और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस समय हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, तो इस बार चलिए मिलकर एक बेहतर ओरल स्वास्थ्य की ओर भी बढ़ें। रात में मिठाईयाँ खाने के बाद ब्रश करने की आदत विकसित करके हम न केवल अपनी स्माइल की रक्षा कर सकते हैं,

बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि त्योहारों का माहौल अनांदपूर्ण रहे और उसमें दाँतों की कोई समस्या न हो। हम सोने से पहले ब्रश करने के वैज्ञानिक महत्व पर बल देकर अपने देश में दाँतों के स्वास्थ्य के मानक बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाना चाहते हैं।'

फिल्म के बारे में: इस फिल्म में सोने से पहले ब्रश न करने की आदत पर रोशनी डाली गई है। इस आदत के कारण दाँतों में कैविटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस फिल्म में विभिन्न पृष्ठभूमियों लोग दिखाए गए हैं, जो मज़ेदार ढंग से मिठाईयों से अपने दाँत 'ब्रश' कर रहे हैं। आखिरी शॉट में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है, जो हर किसी को फ्लैप्परहूप की आदत अपनाने की प्रेरणा दे रहा है। यह फिल्म देश में 'दाँतों के स्वास्थ्य' में सुधार लाने के लिए रिलीज़ की गई है।

सभी आगंतुकों को एक नया ऑटोमोटिव अनुभव देते हुए, हीरो प्रीमियम में आधुनिक वास्तुकला, आकर्षक डिजाइन और नए

जमाने की आकर्षक डिजिटल तकनीकें मौजूद हैं। पेशेवर रूप से प्रशिक्षित बिक्री सलाहकारों की एक टीम स्वामित्व का बेहतरीन प्रीमियम अनुभव प्रदान करते हुए ग्राहकों को उनकी मोबाइलिटी से जुड़ी जरूरतों के मुताबिक व्यक्तिगत बिक्री सुझाव देगी।

हीरो प्रीमियम हीरो मोटोकॉर्प के प्रीमियम उत्पादों

की शृंखला प्रदर्शित करेगा, जिसमें नई लॉन्च की गई फ्लैगशिप मोटरसाइकिल करिज?मा एक्सएमआर भी शामिल है। शहरी यात्रियों के लिए एक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करते हुए, हीरो प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोबाइली समाधानों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करते हुए बीडा वी1 स्कूटर भी प्रदर्शित करेगा। ग्राहक हीरो मोटोकॉर्प की पहली

को-डेवलप्मेंट मोटरसाइकिल हार्ले-डेविडसन एक्स440 का अनुभव भी कर सकते हैं।

इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए हीरो मोटोकॉर्प की भारत बिजनेस यूनिट के चीफ बिजनेस ऑफीसर रंजीवजीत सिंह ने कहा, 'भारत में अपनी पहली प्रीमियम डीलरशिप के सुभारंभ के साथ हम न केवल अपनी अलग-अलग मोटरसाइकिलों और स्कूटरों के मॉडल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि हम आवागमन के साधानों के भविष्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रीमियम, नवीन और स्थायी हैं। जित वर्ष 24 में हमारी कंपनी पूरे भारत में अपने प्रीमियम रिटेल अनुभव को मजबूत करने का काम करेगी।'

ओप्पो इंडिया की सेंड-इन रिपेयर सेवा का विस्तार 25,000 पिन कोड्स तक हुआ रिपेयर के लिए 24 घंटे के टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) की घोषणा की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ओप्पो इंडिया ने अपने सर्विस सेंटर 3.0 के साथ आप्टर-सेल्स सेवा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ओप्पो की पिक-अप और ड्रॉप सेवा के साथ सर्विस सेंटर 3.0 भारत में 25,000 पिन कोड्स तक पहुंच चुका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ओप्पो ने सॉफ्टवेयर समस्याओं, स्क्रीन और बैटरी के रिप्लेसमेंट, स्पीकर डैमेज और टचस्क्रीन खराब होने सहित स्मार्टफोन रिपेयर के 80% मामलों के लिए त्वरित 24-घंटे टीएटी (टर्नअराउंड टाइम)

गारंटी देने के लिए अपनी कार्यक्षमता को मजबूत किया है। पिछले साल शुरू की गई ओप्पो की कस्टमर सर्विस 3.0 से वो पहले से ही ग्राहकों को खास डिवाइसेज के लिए एक घंटे में ऑनसाइट रिपेयरिंग, नए उत्पादों का प्रदर्शन, मुफ्त पिक-अप एवं ड्रॉप और रिपेयर के लिए डेबिट/क्रेडिट कार्ड द्वारा बैंक ईएमआई के विकल्प जैसे कई फ्रायदे प्रदान करती है। ग्राहक ओप्पो के तकनीशियनों को अपनी आँखों के सामने डिवाइस ठीक करते हुए देख सकते हैं, इसलिए ओप्पो इंडिया की इस

सेवा द्वारा पारदर्शी और रियल-टाइम में रिपेयरिंग की सुविधा मिलती है। ग्राहक ओप्पो इंडिया की वेबसाइट पर जाकर 24 घंटे में सेंड-इन रिपेयर सेवा का लाभ लेने के लिए सेंड-इन रिपेयर कॉर्म जमा करके अपने स्मार्टफोन के लिए मुफ्त पिक-अप और ड्रॉप की सेवा प्राप्त कर सकते हैं; इस फॉर्म में उन्हें पिक-अप के पते के साथ डिवाइस का इंटर्न बॉर और अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर डालना होता है। यह डिवाइस सर्विस सेंटर में पहुंचते ही ओप्पो इंडिया का 24

घंटे में रिपेयर का टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) शुरू हो जाता है। रिपेयर के अपडेट्स लगातार ग्राहकों को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से मिलते रहते हैं। यदि रिपेयर होने वाली डिवाइस किसी दूर-दराज के इलाके से आई है, तो पिक-अप से लेकर रिपेयर और डिलीवरी तक की प्रक्रिया 5 से 7 दिनों में पूरी हो जाती है। ओप्पो इंडिया के ग्राहक ट्रिक्टर या फेसबुक पर @OPPOCareIN से संपर्क करके भी सेंड-इन रिपेयर सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सर्विस सेंटर के

विस्तार के

एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने की मर्जर कि घोषणा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
लिमिटेड (AU SFB) के
निदेशक मंडल और फिनकेयर
स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के
निदेशक मंडल ने कल 29
अक्टूबर को आयोजित अपनी-
अपनी बैठकों में एयू एसएफबी
और फिनकेयर एसएफबी के आल
स्टॉक मर्जर को मंजूरी दे दी है।
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की
धारा 44ए के तहत विलय की
योजना एयू एसएफबी और
फिनकेयर एसएफबी के शेयरधारकों
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत
भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय
प्रतिस्पर्धा आयोग के अनुमोदन के
अधीन है। जरूरी अप्रूवल मिलने के
पर फिनकेयर एसएफबी का एयू
एसएफबी में विलय हो जाएगा और
फिनकेयर एसएफबी के शेयरधारकों

रीसाइकल्ड फाइबर उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
सैक्ससेल और बिड़ला सेल्यूलोज़ ने सर्कुलरिटी में तेजी लाने के लिए

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टेक्सटाइल रीसाइकिलिंग इनोवेटर सैक्ससेल ने मैन मेड सेल्यूलोसिक फाइबर के दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक, आदित्य बिड़ला समूह के बिड़ला सेल्यूलोज़ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू रीसाइकल्ड मैन मेड सेल्यूलोसिक फाइबर के उत्पादन के लिए दोनों कंपनियों के बीच सहयोग के विस्तार का मार्ग मजबूत करता है। सैक्ससेल की टेक्सटाइल वेस्ट पल्टिंग तकनीक को बिड़ला की एडवांस वेट स्प्रिंगिंग की विशेषज्ञता के साथ मिलाकर उच्च गुणवत्ता वाले सर्स्टेनेबल 'सैएक्ससेल' रीसाइकल्ड फाइबर द्वारा बनाया जाता है जो वरिजियक स्तर पर ग्राहकों की सर्कुलर टेक्सटाइल आवश्यकताओं को पूरा करता है।

इस पर टिप्पणी करते हुए, सैक्सेल के सीईओ श्री एरिक वैन डेर वेर्ड ने कहा कि यह सहयोग पार्टनरशिप और आपसी प्रतिबद्धता के आधार पर एक मजबूत सर्कलर

મંબાર્ડી આઈપીટી ચેટવાર્ક

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल/ कोटक) ने आज नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। यह साझेदारी एनईएसएल के प्लेटफॉर्म पर केएमबीएल की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) जारी करने के लिये हुई है। इस साझेदारी से व्यापार (ट्रेड) का डिजिटाइजेशन हो सकेगा और कागजों पर बैंक गारंटीज का इश्योएस बंद करने में

ज्ञामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, १३, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं १८, सेक्टर-ठी-२, सांवर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइप्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है।

को अनुमोदित शेयर स्वैप रेश्यो पर फिनकेयर एसएफबी में उनके शेयरों के बदले एयू एसएफबी के शेयर मिलेंगे। फिनकेयर एसएफबी के सभी कर्मचारी एयू एसएफबी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे।

एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी के बोर्ड ने एक-दूसरे के बिजनेस ऑपरेशन के प्रमुख पहलुओं के उचित परिश्रम के परिणामों पर विचार किया। शर्तों के अनुसार, फिनकेयर एसएफबी के प्रमोटर फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड (**FBSL**), विलय के पूरा होने से पहले फिनकेयर एसएफबी में 700 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी द्वारा नियुक्त इंडीपेंडेंट वैल्यूअर्स यानी मल्यांकनकर्ताओं,

बंसी एस मेहता वैल्यूअर्स एलएलपी और आरबीएसए वैल्यूएशन एडवाइजर्स एलएलपी ने शेयर एक्सचेंज रेश्यो की सिफारिश की है, जिसे संबंधित बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड ने शेयर एक्सचेंज रेश्यो पर एयू एसएफबी को निष्पक्षता राय प्रदान की आई। आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने फिनकेयर एसएफबी को निष्पक्ष राय प्रदान की। इसके अनुसार, फिनकेयर एसएफबी शेयरधारकों को पिनबोरेयर एसएफबी के 2,000 शेयरों के लिए एयू एसएफबी में 579 शेयर प्राप्त होंगे। विलय के बाद, फिनकेयर एसएफबी के मौजूदा शेयरधारकों की एयू एसएफबी में 9.9% हिस्सेदारी होगी। आईसीआईसीआईसीक्योरिटीज लिमिटेड और अर्पणवृद्धि

कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (Arpwood Capital Pvt Ltd) ने लेनदेन पर फिनकेयर एसएफबी के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया और एम्बिग्राइवेट लिमिटेड और मिरे एसेक्युरिटीज़ कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने एयू एसएफबी के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया। एजेंडबी एंड पार्टनर्स ने एसएफबी के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया और एनाग्राइवर पार्टनर्स ने फिनकेयर एसएफबी के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया। केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी ने क्रमशः एयू एसएफबी और फिनकेयर एसएफबी के लिए डिलिजेंस एडवाइजर यानी परिश्रम सलाहकार के रूप में काम किया।

फिनकेयर एसएफबी के एमडब्ल्यू
और सीईओ राजीव यादव को विलय

के बाद एयू एसएफबी का डिप्टी सीईओ नियुक्त किया जाएगा। वह एयू एसएफबी के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल को रिपोर्ट करेंगे। यादव एयू एसएफबी विफिनकेयर इकाई का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, जिसमें फिनकेयर एसएफबी के अधिकांश बिजेनेस होंगे। इसके अलावा, वह विलय के बाद आईटी इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एयू एसएफबी के एमडी और सीईओ के साथ संयुक्त रूप एयू एसएफबी की आईटी और डिजिटल इकाई का नेतृत्व करेंगे।

अपनी नई भूमिका में, यादव एयू एसएफबी की बोर्ड बैठकों में आमंत्रित सदस्य होंगे। फिनकेयर एसएफबी के बोर्ड में नामांकित निदेशक, दिव्या सहगल, विलय के बाद स्मृथ इंटीशेन और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एयू एसएफबी के बोर्ड में शामिल होंगी। वर्तमान में एयू एसएफबी के कार्यकारी निदेशक उत्तम टिबरेवाल को मर्ज की गई इकाई में एयू एसएफबी के एजीक्यूटिव डायरेक्टर और डिप्टी सीईओ के रूप में पदोन्नत किया जाएगा।

शक्ति पंप्स को सातवां पेटेंट वेस्ट वाटर पम्प के लिए मिला

पीथमपरा आईपीटी नेटवर्क

एनर्जी एफिशिएंट पंप्स और मोटर्स निर्माण की अग्रणी शक्ति पंप्स (इंडिया) लिमिटेड को वेस्ट वाटर पंप्स में “एडजस्टेबल इम्पेलर के साथ ग्राइंडर पंप असेंबली” का अविष्कार करने के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार ने, 1970 के पेटेंट अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करते हुए, शक्ति पंप्स को यह पेटेंट प्रदान किया है। यह पेटेंट 20 वर्षों की अवधि के बैध है यह और यह शक्ति पंप्स का सातवां पेटेंट है। इस इनोवेशन के विभिन्न लाभ हैं। इसमें एडजस्टेबल इम्पेलर के साथ कठर अरेंजमेन्ट का उपयोग किया गया है। जिससे ठोस मटरेयिल का आकार छोटा किया जाएगा, ताकि आगे की प्रोसेस सरलता से हो पाए। अपशिष्ट जल में ठोस पदार्थ को काटने और पीसने से, यह तकनीक छोटे कणों का उत्पादन करती है जो कणों को तली में एकत्र करता है एवं जैविक उपचार, फिल्टरेशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसी डाउनस्ट्रीम प्रक्रियाओं को सरल बनाता है। इससे अपशिष्ट जल उपचार और औद्योगिक प्रक्रियाओं की क्षमता में काफ़ी सुधार होगा। शक्ति पंप्स के चेयरमेन दिनेश पाटीदार ने नई पेटेंट टेक्नोलॉजी के बारे में कहा कि “मुख्य रूप से ठोस अपशिष्ट के कारण अपशिष्ट जल लाइनों में रुकावटों का समाना करना पड़ता है। ये रुकावटें सामान्य परिचालन को कठिन बनाती हैं और इसके परिणामस्वरूप स्खरखाव में भारी लागत आ सकती है। हमारी रिसर्च टीम द्वारा किये गए इस शोध और उस पर मिले इस नए पेटेंट के माध्यम से, हम इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से कम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम रुकरखाव की आवश्यकताएं होती हैं और ऑपरेशनल डाउनटाइम कम हो जाता है। यह तकनीक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लॉटों और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए एक सस्टेनेबल विकल्प है। इसके अलावा इस पेटेंट का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रंखला में किया जा सकता है जहां पर ठोस कणों के आकार को कम करने की आवश्यकता होती है।

कोटक महिन्द्रा बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिये नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की

મંબાઈ | આઈપીટી ચેટવકર્તા

मदद मिलेगी। इस डिजिटाइजेशन में बीमा, संशोधन, समापन, डिजिटर स्ट्रैपिंग और हस्ताक्षर शामिल हैं, जिससे गारंटी का टर्नअराउंड टाइ (टीएमटी) कुछ ही घंटों का हो जाता है, जबकि कागज वाली प्रक्रिया 2-3 कार्यदिवस लगते हैं। ई-बीजी में सत्यापन के जोखिम भी नहीं रहते हैं। कोटक महिन्द्रा बैंक के प्रेसिडेंट एवं होलसेल बैंकिंग के हेड परिस्तोकशयप ने कहा, ‘कोटक महिन्द्रा बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा तथा आसानी देने में आगे रहा है। एनईएसएल के साथ साझेदारी

करके हमारे व्यापार प्राहकों को ई-बीजी मिलेगी और सत्यापन के विभिन्न चरणों सहित असीमित कागजी कार्यवाही में लेंडर तथा जारीकर्ता को जो समस्याएं होती हैं, वे दूर होंगी। प्राहकों पर केन्द्रित होने और नवाचार पर ध्यान देकर हमने अपनी बैंकिंग सेवाओं में डिजिटल कायाकल्प को काफी पहले अपनाया है। हम बैंकिंग उद्योग में अपने द्वारा प्रदत्त सभी उत्पादों तथा सेवाओं में अपने प्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिये प्रतिबद्ध हैं और ई-बीजी इनमें से एक है।'